

## उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंजूरी सहित लयि गए कई महत्त्वपूर्ण नरिणय

### चरचा में क्यों?

20 दसिंबर, 2022 को उत्तराखण्ड सचवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सहि धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी सहित 20 परस्तावों को हरी झंडी मली।

### परमुख बदि

- कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंजूरी से प्रदेश की नदियों, नालों और खालों से करीब 20 हजार मेगावाट बजली उत्पादन की क्षमता का दोहन करने की राह आसान हो गई है। नीतहिमाचल प्रदेश की जलवदियुत नीतहि 2022 के अनुरूप बनाई गई है।
- इस नीतहि से अब प्रदेश में जहाँ नए नविशकों को 25 लाख रुपए की जगह सरिफ एक लाख रुपए वकिसा शुल्क देना होगा तो वही पुरानी अटकी योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर कयि जा सकेगा। परयोजना की खुदाई के दौरान नकिलने वाले माल से ही नरिमाण कार्य कर सकेंगे, स्टोन क्रशर भी लगा सकेंगे।
- प्रोजेक्ट की अवधिसके संचालन से मानी जाएगी। 25 मेगावाट तक के सभी प्रोजेक्ट का यूपीसीएल को अनविरय पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीपी) करना होगा।
- राज्य कैबिनेट द्वारा लयि गए कुछ अनय महत्त्वपूर्ण नरिणय -
  - कैबिनेट ने औद्योगकि उत्पादों को बाहर ले जाने के लयि उत्तराखण्ड लॉजसि्टकिस नीतहि 2022 को मंजूरी दे दी। इससे गोदामों, अंतरदेशीय कंटेनर डपि (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगकि संपदाओं, क्लसटरों से रेल-सड़क कनेक्टविटी जैसे नए और मौजूदा लॉजसि्टकिस बुनयिदी ढाँचे को मजबूती मलिंगी। परवतीय-मैदानी क्षेत्रों के बीच आरथकि संबंध मजबूत होंगे। वेयर हाउस बनाने की राह आसान होगी।
  - कैदियों को अब परजिनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र-पुत्री के वविह के लयि 15 दनि की पैरोल डीएम के सत्र से मलि सकेगी। पहले मंडलायुक्त को यह अधकिर था। इसके लयि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड (बंदियों के दंडादेश का नलिबन, संशोधन) नयिमावली को मंजूरी दी।
  - प्रदेश के सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वतितीय वर्ष 2023-24 में नःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसकी योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे करीब एक लाख छात्रों को लाभ मलिंगा।
  - प्रदेश में नःशुल्क वयक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्तहि, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपए स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 परतशित की छूट देने का फैसला लयि गया है। यह छूट जीवनकाल में दो बार ही मलिंगी।
  - यूनविरसिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनविरसिटी करने पर मुहर।
  - 20 राजकीय औद्योगकि प्रशकिषण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचा के हिसाब से अपग्रेड कयि जाएगा।
  - राज्यों के लयि पूंजीगत नविश की वशिष सहायता योजना के तहत परविहन वभिग को कुछ सुधार करने पर आरथकि सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत-परतशित और परविहन नगिम की परवतीय क्षेत्रों में संचालति बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 परतशित की गई।
  - उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखण्ड सरकार ने भी रेल भूमिवकिसा में भू-उपयोग परविरतन की शरत को खतम कर दयि है। स्थानीय नकिया व प्राधकिरण तालमेल बनाकर रेल वकिसा योजनाओं में काम करेंगे।
  - लखवाड बहुदेशीय परयोजना के तहत 75 करोड रुपए के कार्यों की ई-नविदि में केवल एल एंडटीका टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति।
  - औद्योगकि संबंध संहति 2020 के तहत उत्तराखण्ड औद्योगकि संबंध नयिमावली 2022 को मंजूरी। इसमें मुख्यतः वयापार के सरलीकरण और उद्योगों को अनुकूल वातावरण देने के साथ कर्मचारी हतियों को भी समयबद्ध तरीके से दए जाने के संबंध में प्रावधान कयि गए हैं।
  - उत्तराखण्ड राजस्व परषिद अनुभाग अधकिारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनकि) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनकि) सेवा नयिमावली 2022 को मंजूरी।
  - बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज पर अलमोडा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लयि भी मास्टर प्लान बनेंगे।
  - उत्तराखण्ड के वधिानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।

